

शिक्षक - रवि शंकर राय, विषय - अर्थशास्त्र
दिनांक - 02-07-2020, वर्ग - B.A - II

जन्म दर ऊंची होने के कारण (Causes of the High Birth Rate)

भारत में जन्म दर अब भी ऊंची है और यह आशा कि परिवार नियोजन के फलस्वरूप यह नीची होगी, निराधार सिद्ध हुई है। पिछले छः दशकों में भारत में जन्म दर में विशेष कमी नहीं हुई है। 1961 में भारत में कुल जननक्षमता दर (total fertility rate) 6.11 प्रति महिला थी जो 2001 तक कम होते-होते 3.50 प्रति महिला और 2010 में 2.5 प्रति महिला रह गई। निश्चय ही यह महत्वपूर्ण निरावट है परन्तु अभी भी यह दर बहुत ज्यादा है। इसका कारण यह है कि इस देश में अनेक आर्थिक और सामाजिक कारक ऊंची जननक्षमता के पक्ष में हैं।

आर्थिक कारक (Economic factors) - मनुष्य के व्यवहार पर आर्थिक वातावरण का काफी प्रभाव होता है यहां तक कि जननक्षमता भी आर्थिक कारकों से प्रभावित होती है। ये आर्थिक कारक हैं कृषि की व्यापकता, शहरीकरण का नीचा स्तर और गरीबी की व्यापकता। अब हम विचार करेंगे कि इन कारकों ने भारत में जन्म दर को नीचे गिराने से किस तरह रोका है।

1. कृषि की व्यापकता - भारत का मुख्य व्यवसाय कृषि है। खेती में लगे हुए लोगों के लिए बालक लम्बे असें तक भार नहीं होते। छोटी आय हो वे पशुओं को चराने, खेतों की रखवाली करने, निर्राई करने आदि में पिता का हाथ बंटाने लगते हैं। इसलिए किसान अधिक सन्तान को बुला समझते। लेकिन यह तर्क दिया जा सकता है कि जिस देश में वेरोजगारी और अल्प-रोजगार व्यापक हो वहां बाल-श्रम की परिचा के लिए ज उपयोगिता नहीं होगी। लेकिन इस तर्क में कोई सच्चाई है या नहीं इसे समझने के लिए हमें कृषि कार्य के स्वरूप को समझना होगा। भारत में जहां के तकनीक पिछड़े हैं और जहां कृषि कार्य में जुलाई और फसलों की कटाई, निर्राई आदि के लिए ज्यादा श्रम की आवश्यकता होती है वहां बाल की उपयोगिता से इनकार नहीं किया जा सकता। इस तथ्य को ध्यान में रखकर ही ग्रामीण श्रम जांच समिति (Rural Labour Enquiry Commi ने लिखा है कि कृषि के बहुत व्यस्त मौसम में अनेक स्थानीय क्षेत्रों में श्रम की कमी हो जाने से श्रम बाजार में बाल श्रम की खपत हो जाती है।¹⁵ स्थिति में जन्म दर ऊंची होना स्वाभाविक है।

2. शहरीकरण का नीचा स्तर - पश्चिमी देशों की तुलना में भारत में शहरों की संख्या और उनमें रहने वाली जनसंख्या का अनुपात बहुत व भारत में 31 प्रतिशत शहरी जनसंख्या की तुलना में इंग्लैंड की जनसंख्या का 90 प्रतिशत से अधिक भाग शहरों में निवास करता है। शहरों में की समस्या, बच्चों का महंगा लालन-पालन, संयुक्त परिवार का टूटना आदि वे बहुत सारे कारण हैं जिनसे जन्म दर में कमी होती है। अनेक का विचार है कि भारत में जैसे-जैसे औद्योगिकरण बढ़ेगा जन्म दर में कमी होगी। लेकिन रोबर्ट कैसन (Robert Cassen) के अनुसार "भारत शहरीकरण हुआ है उसके साथ इस प्रकार के सामाजिक परिवर्तन नहीं हुए हैं जो जन्म दर को नीचे लाते हैं। दरअसल समाजशास्त्रीय अध्ययनों के ग्रामीण जीवन की सामाजिक व्यवस्था और वहां का पारिवारिक ढांचा कस्बों अथवा शहरों में आश्चर्यजनक ढंग से जीवित है।"¹⁶

3. गरीबी की व्यापकता - अल्पविकसित देशों में व्यापक गरीबी, उच्च जन्मदर का एक मुख्य कारण है। पहमूद ममदानी ने लिखा है, "लोग गरीब नहीं हैं कि उनके परिवार बड़े हैं। इसके विपरीत, उनके परिवार इसलिए बड़े होते हैं, क्योंकि वे गरीब हैं।"¹⁷ अब हम भारत में ऊंची दर के पीछे आर्थिक तार्किकता को समझने की कोशिश करेंगे। परिवार की आय का स्तर नीचा होने पर परिवार में एक अतिरिक्त बच्चे के ल पर आने वाले खर्च की तुलना में उससे प्राप्त होने वाले फायदे ज्यादा होते हैं। ये परिवार बच्चों से तीन प्रकार के फायदों की आशा करते हैं हैं - अतिरिक्त आय, सामाजिक सुरक्षा और विभिन्न प्रकार की सेवाएं। विश्व बैंक के प्रकाशन *World Development Report 1984* के "गरीब माता-पिताओं के लिए बच्चों की परवरिश की लागत नीची होने के ठोस कारण हैं। बच्चों से आर्थिक (और अन्य) लाभ ज्यादा हैं, ज्यादा बच्चे होना आर्थिक दृष्टि से विवेकपूर्ण है।"¹⁸ इस मत की पुष्टि गुनार मिर्दाल (Gunnar Myrdal) ने भी की है। उनके अनुसार "में बच्चे भार नहीं होते। इसके विपरीत, अक्सर वे व्यक्ति के लिए सामाजिक सुरक्षा का एकमात्र साधन होते हैं।"¹⁹

* Institutional change or Institutional structure - 6 Land Reforms, Farm size and Productivity.

संस्थागत सुधारों के बिना तकनीकी उन्नति सम्भव नहीं है। संस्थागत नीतियों द्वारा ही कृषि-उत्पादकता बढ़ सकती है। भारत में स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् निम्न संस्थागत नीतियाँ अपनाई गई हैं-

1. जमींदारी प्रथा का उन्मूलन (Abolition of Zamindari and Other Intermediators)— स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् जागीरदारों और बँटवाईदारों आदि मध्यस्थों का देश की भूमि के 40% भाग पर अधिकार था। काश्तकारों के शोषण तथा कृषि के पिछड़ेपन का यही कारण था। पहली तथा दूसरी योजना में इन सभी मध्यस्थों का अन्त किया गया। इससे लगभग 2½ करोड़ से अधिक काश्तकार मालिक बन चुके हैं। उनका सरकार से सीधा सम्बन्ध स्थापित हो चुका है। परिणामस्वरूप बहुत-सी कृषि योग्य बेकार भूमि सरकार के हाथ में आ गई। इस भूमि पर भूमिहीन किसानों को बसाया गया है। इससे कृषि-क्षेत्र और उत्पादन में भी वृद्धि हुई है।

2. भूमि की उच्चतम सीमा निर्धारण (Ceiling on Land Holdings)—इसका अभिप्राय यह है कि एक परिवार के व्यक्ति के लिए खेती योग्य भूमि की एक सीमा निर्धारित कर दी जाती है। इसलिए भारत में विभिन्न राज्यों में

कृषि जोतों की उच्चतम सीमा निर्धारित करने के उद्देश्य से कानून लागू किए गए। इसके मुख्य उद्देश्य थे—(i) कृषि वितरण में असमानता को दूर करना, (ii) आय की असमानताओं को कम करना, (iii) भूमिहीनों को भूमि दिलवाना (iv) भूमि को बँटाई पर देने की प्रथा को समाप्त करना।

3. काश्तकारी सुधार (Tenancy Reforms)—काश्तकारी व्यवस्था में भूमि का स्वामी स्वयं खेती नहीं करता अपितु किराए पर खेती करवाता है। विभिन्न जमींदारी उन्मूलन अधिनियमों में यह छूट दी गई थी कि विधवाएँ, अवयस्क, सैनिक या असमर्थ लोग अपनी भूमि को लगान पर दूसरों से खेती करवा सकते हैं। इसे काश्तकारी या पट्टेदारी व्यवस्था कहते हैं। भारत में 40% खेती इसी तरह की जाती है। भारत में ऐसे काश्तकारों की दशा अच्छी न थी। इनकी दशा सुधारने के लिए निम्न कानून बनाए गए :

(i) लगान से छूट (Exemption from Rent)—प्राकृतिक प्रकोप के समय जब सरकार भू-स्वामियों का लगान माफ करती है तो काश्तकारों का लगान भी स्वयं माफ होगा।

(ii) भूमि से बर्दखल नहा (No Eviction from Land)—काश्तकार का भूमि स गर-कानूना ढग से बर्दखल नहीं किया जा सकता।

(iii) काश्तकार का मुआवजा (Compensation to Tenants)—जब काश्तकार स्वच्छा स भूमि छाडता है तो उसने भूमि पर जो स्थायी सुधार किए थे, जैसे—कुआँ बनवाने, इमारत बनवाने, मेंडें या नालियाँ बनवाने आदि का मुआवजा 1 दया जाएगा।

(iv) लगान का निर्धारण (Fixation of Rent)—काश्तकारों से भूमि उपज का 1/4 या 1/5 भाग ही लगान के रूप में लिया जा सकता है।

(v) उपहारों पर रोक (Check on Gifts)—काश्तकारों से बंकार या उपहार लेना गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया है।

(vi) कुर्की नहीं (No Attachment)—यदि किसी काश्तकार ने लगान न दिया हो तो उसके पशु, औजार तथा खड़ी फसल की कुर्की नहीं की जा सकती।

4. सहकारी खेती (Co-operative Farming)— भारतीय सरकार ने सरकारी खेती को भी प्रोत्साहन दिया है। इसके अन्तर्गत छोटे-छोटे भू-खण्डों के स्वामी अपनी भूमि और दूसरे कृषि-यन्त्र मिलाकर तथा मिल-जुलकर खेती के कार्य करते हैं। परिणामस्वरूप (i) किसानों के खेत बड़े हो जाते हैं, (ii) वे अच्छे बीज, खाद, सिंचाई यन्त्रों का प्रयोग करते हैं। (iii) वे मध्यस्थों के शोषण से बच जाते हैं। (iv) कृषि उत्पादन बढ़ता है, (v) किसानों की आय बढ़ती है। (vi) उनका जीवन-स्तर ऊँचा होता है।

5. चकबन्दी (Consolidation of Land Holdings)— चकबन्दी से तात्पर्य भूमि की उस व्यवस्था से है जिसमें एक ही किसान के स्वामित्व में अलग-अलग स्थानों पर बिखरे हुए भूमि के टुकड़ों को एक स्थान पर इकट्ठा किया जाता है तथा उसे एक बड़े खेत में बदल दिया जाता है।

पहली पंचवर्षीय योजना में चकबन्दी का काम आरम्भ हो गया था। सभी राज्यों में चकबन्दी की प्रगति समान रूप से नहीं हुई है। हरियाणा और पंजाब में चकबन्दी का कार्य पूरा हो चुका है। उत्तर प्रदेश में पूरा होने को है। अब तक 620 लाख हेक्टेयर भूमि पर चकबन्दी की जा चुकी है।

भारत में कृषि संस्थागत नीतियाँ
या
भूमि सुधार

1. जमींदारी प्रथा का उन्मूलन
2. भूमि की उच्चतम सीमा निर्धारण
3. काश्तकारी सुधार
4. सहकारी खेती
5. चकबन्दी
6. भूदान आन्दोलन